राजीव गांधी आवास योजना के पहले चरण को मिली कैबिनेट की हरी झंडी

शहरी गरीबों को पक्का मकान

नई दिल्ली। विशेष संवाददाता

केंद्र सरकार ने शहरों के झुग्गीवासियों को पक्के मकान देने के लिए राजीव गांधी आवास योजना के पहले चरण को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत केंद्र सरकार 50 फीसदी सहायता उपलब्ध कराएगी। राज्य सरकारें घर बनाकर कम कीमत पर उपलब्ध कराएंगी। योजना देश के 250 शहरों के लिए होगी जिनकी आबादी एक लाख या इससे ज्यादा है। इसके अलावा, अनुसूचित जनजाति के बच्चों को मिलने वाली छात्रवृत्ति में करीब 70 फीसदी की वृद्धि की गई है। साथ ही, अब दो लाख तक की आय वाले अभिभावकों के बच्चे भी छात्रवृत्ति के हकदार होंगे, जबकि पहले यह सीमा 1.45 लाख थी।

प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। विभिन्न कक्षाओं के हिसाब

से छात्रवृत्ति चार समूहों में दी जाती है। पहले समूह में 330 रुपये महीने से बढ़ाकर 550 रुपये की गई है, जबकि होस्टल में रहने वाले छात्रों के लिए यह 740 से बढ़ाकर 1200 रुपये प्रतिमाह की गई है।

दूसरे समूह में 330 से 530 रुपये तथा होस्टल के लिए 510 से 820 रुपये, तीसरे में 185 से 300 रुपये तथा होस्टल के लिए 355 से 570 रुपये और चौथे समूह में 140 से 230 रुपये तथा होस्टल के लिए 235 से 380 रुपये प्रतिमाह की गई है। इसके अलावा स्टडी टूर, कोचिंग, विकलांग छात्रों को

फैसले

- एक लाख या अधिक आबादी वाले 250 शहरों के लिए योजना
- राज्य सरकारें कम कीमत पर मुहैया कराएंगी घर, केंद्र करेगा मदद
- आदिवासी छात्रों की छात्रवृत्ति बढ़ी, 1 जुलाई से लागू होगी वृद्धि

सहायता उपलब्ध कराने आदि के भत्तों में भी 60-70 फीसदी तक वृद्धि की गई। यह वृद्धि 1 जुलाई 2011 से लागू होगी।

ओबीसी में और जातियां

केंद्र सरकार की सेवाओं में आरक्षण का लाभ देने के लिए कैबिनेट ने 14 राज्यों में कुछ अन्य जातियों और समुदायों को पिछड़ी जातियों की केंद्र की सूची में शामिल करने को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रस्ताव में आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित अंडमान निकोबार एवं पुडुचेरी की कुछ और जातियों को ओबीसी में शामिल करने की सिफारिश की गई थी। सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय जल्द इस बाबत आवश्यक संसोधन अधिसूचना जारी करेगा।

शौचालय निर्माण की राशि बढ़ी- स्वच्छता अभियान के तहत गरीब परिवार को शौचालयों के निर्माण के लिए मिलने वाली राशि में 1,000 रुपये की वृद्धि की गई है। बीपीएल परिवारों को अब इसके लिए 3200 रुपये मिलेंगे, जबकि पर्वतीय क्षेत्र के लिए यह 3700 रुपये होगी। इससे केंद्र सरकार के खजाने पर 1,348 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय आएगा।